

10-11-15

पंजावली प्रस्तुत । पूर्व नियत दिनांक को
बहस सुनी गई थी। अधीनस्थ के विधान
अभिधापक ने बहस में बताया कि तरतबी
रेस्पोण्डर को मुलु दि 23-2-04 में
हो गयी थी। उसके कारिनात को रिपोर्ट
पर लेने के लिए दि 9.7.04 को
प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था कि
उसकी पत्नि व शव्यक्त बच्चों को
रिपोर्ट पर लिया जावे। पूरा डाका
ही शेक्टर का रकारिज कर दिया
गया है जबकि मुलु तरतबी रेस्पो
धा उससे कोई रिलिक भी नहीं
चाहिए था मुलु के हड तक ही डाका
शेक्टर किया जाना चाहिए। अधीन
स्थ का कर अधीनस्थ न्यायालय को
सुनवाई हेतु लिखा जावे।
रेस्पोण्डर के 'अभिधापक का
बहस में जवाब है कि वादा का घट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख से जारी हुए
	<p> दायित्व था कि 30 दिन में कार्रवाई को रिपोर्ट न लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते अतः दावा स्वतः ही अकेले माना जाता है अर्जिट 22(3) के अन्तर्गत अकेले को अर्जिट करने हेतु न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अपिलर ने 22(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लापरवाही एवं अक्षमता की श्रेणी में अर्जिट है। स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है अतः अपिलरवाजि की जावे। अपिलर के अतिरिक्त के जजस जब्बाबुलजवाब में बताते कि दि. 23-2-04 को कार्रवाई का वकालतनामा प्राप्त हो गया था रिसपोडेंट का भी दायित्व था कि वह में न्यायालय को सूचित करे। हमने विद्वान अतिरिक्त को जजस पर भरोसा किया। अर्जिट 22(4) (3) भूलतः इस प्रकार है। " जहाँ विधि द्वारा परिभाषित समय के भीतर कोई अर्जिट </p>	

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>शिलावा</p>	<p>उपनिधम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वही वाद का, जहाँ तक वह गुन प्रतिवादी के विरुद्ध है, उपशमन हो जायेगा। इन आवधानों से स्पष्ट है कि पूरा दावा अकेल नहीं होकर केवल गुन प्रतिवादी के विरुद्ध ही उपशमन होगा। गुनक नरतीबी रेस्का है जिसके खिलाफ कोई रिजिक नहीं चढ़ाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में पूरा दावा ही अकेल मानकर खारिज किया है कि: इस अदेश को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है केवल दावा गुनक के विरुद्ध ही अकेल होगा। ऐसी स्थिति में नेपाल सरकार का अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि गुनक के शेषा प्रतिवादीगण को सुनवाई कर अथवा अदेश पारित कर देने पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.11.15 को उपस्थित होकर अपनी 2 पैरवी सुनिश्चन करें। अदेश राज दिनांक 10.11.15 को सुनाया गया।</p>	

प्रमुख अधिकारी
जज अलवर